

manufacturing fans and fractional horse power motors and the state of this unit is being reviewed. As far as possible we shall try to take it over for the purpose of running it. As regards compensation, there is no question of compensation when we take over the management. It is only when we nationalise that the question of compensation will arise.

SHRI SAMAR GUHA : I want to know from the hon. Minister whether the Ganesh Flour Mills Co. Ltd. at Delhi were formerly shifted from Pakistan. If so, whether it got compensation for its evacuated property. If so, what is the reason that recently a year before according to enemy properties declared in Pakistan an *ex-gratia* compensation to the extent of Rs. 27 lakhs given to this company?

What are the reasons for it, and what are the facts thereabout?

SHRI C. SUBRAMANIAM : A sum of Rs. 25 lakhs was received as compensation for the company's properties in Pakistan....

SHRI SAMAR GUHA : Rs. 27 lakhs.

SHRI C. SUBRAMANIAM : It had its own units in Pakistan also. Most of this amount of Rs. 25 lakhs was utilised for paying off arrears of income-tax, wages etc.

SHRI SAMAR GUHA : My first question has not been answered namely whether it was totally transferred at the time of partition or it continued up to the 1965 Indo-Pak war and if not, how they were entitled to get Rs. 27 lakhs as *ex-gratia* compensation.

SHRI C. SUBRAMANIAM : As for as my information goes, they had some units in Pakistan also in addition to these five units, and it is for these units that we have received compensation of Rs. 25 lakhs.

SHRI SAMAR GUHA : May I know whether there were companies up to the 1965 war, because this *ex-gratia* compensation is given for properties which

were declared as enemy properties at the time of the 1965 Indo-Pakistan war.

SHRI C. SUBRAMANIAM : I do not have the facts with regard to this. But the fact is that we received Rs. 25 lakhs as compensation. If the hon. Member is interested in having further particulars, he may write to me, and certainly I shall supply the information.

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय आज के प्रश्नों में एक ही सदस्य के नाम से दो प्रश्न 468 और 479 दिये गये हैं। क्या यह कोई नई परम्परा डाली गई है?

अध्यक्ष महोदय : नीचे नोट किया गया है कि वह सवाल ट्रांसफर किया गया है।

SPECIAL PROVISION FOR U.P. for 1974-75

469. **SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL :** Will the Minister of PLANNING be pleased to state .

(a) whether Government have made a special provision, outside the plan, of about Rs. 139 crores for U.P. for 1974-75; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI MOHAN DHARIA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

श्री यमुना प्रसाद मंडल : सारे सदन को मालूम है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग बहुत पिछड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त अन्य पूर्वी राज्य भी बहुत पिछड़े हुए हैं। एक राज्य तो तीसरे स्थान से तेरहवें स्थान पर चला गया है। श्री घर और श्री धारिया इस बात को जानते हैं। यदि इन पूर्वी राज्यों को—खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार और आसाम को विशेष सहायता नहीं दी गई,....

एक माननीय सदस्य : मध्य प्रदेश को।

श्री यमुना प्रसाद मंडल :....तो जिस इम्बेलेस की बात श्री सुब्रह्मण्यम ने कही है वह

कैसे दूर हो पायेगा ? अगर यू० पी० को नहीं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य पूर्वी राज्यों को विशेष सहायता दी जायेगी ?

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI D P DHAR) : The question specifically relates to an enquiry whether a sum of Rs 139 crores is being provided for UP as special grant or fund. This is not true. No special provision has been made of the order of Rs 139 crores for UP, but as far as the question of dealing with the backwardness of certain areas of UP or dealing with certain specific problems of UP is concerned, certainly in the Plan itself provisions have been made adequately for that purpose.

श्री यमुना प्रसाद मंडल प्लानिंग कमीशन ने देश के जिन 54 जिलों को आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बताया है जब इस तरह के विशेष फंडिंग वा एलाटमेंट किया जायेगा ता क्या मंत्री महोदय उन 54 जिला का भी ध्यान करेंगे ?

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर)
जल्द करेंगे ।

श्री सरजू पाडेय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के पाच जिला झांसी, बरेली, बनिया और दो और जिलों को जिनके नाम मुझे याद नहीं है खास तौर से पाचवी पचवर्षीय योजना में डेवलप करने की योजना बनाई गई है और उसके लिये कुछ स्पेशल फंड भी प्रोवाइड किए गए हैं । मेरा कहना यह है कि इसी तरह के और जिले हैं जिनको पटेल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़ा जिला कहा था 15 जिले बह हैं उसमें न आबमगढ़ का नाम है न उलिया का नाम है, न गाजीपुर का नाम है, न बस्ती का या देवरिया का नाम है । तो मैं यह जानना चाहता हू कि यह जो धन सरकार की ओर से दिया जा रहा है खास-तौर से इन जिलों के लिये उसका प्राइ-टीरिया क्या है और उसमें और जिले का नाम किये जायेगे या नहीं ?

SHRI D P DHAR . The hon member has mentioned the state of distress which obtains in five districts, out of which he does not remember the names of two. But taking into account his great concern for these districts, we shall look into this.

SHRI RAM SURAT PRASAD . UP is one of the very backward States, specially the hill regions, Eastern UP and Bundelkhand. Keeping in view the population and poverty, why has this provision not been made? Further, has the UP Government made such a request to the Central Government or not?

Mr SPEAKER The same question was asked by Shri Mandal

SHRI RAM SURAT PRASAD Has the UP Government made such a request ?

SHRI D P DHAR I have nothing to add to the submissions I have already made

तस्करी रोकने के लिए राज्य की सीमा बन्द करने का बिहार सरकार द्वारा अनुरोध

* 470 श्री जगन्नाथ मिश्र क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य की सीमा बन्द करने और कड़े पग उठाने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मागी है, और

(ख) यदि हा, तो केन्द्रीय सरकार ने तस्करी की रोकथाम हेतु बिहार सरकार को किस रूप में सहायता दी है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहम्मद) : (क) और (ख) जनवरी 1974 में जिस समय राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ उस समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की पहले से की गई तैनाती का ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकी । फिर भी हम राज्य से तस्करी को रोकने में सहायता करने के लिये, राज्य सरकार से उसकी